आकाशवाणी शिमला
19.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- कांगड़ा जिला का दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल अगले दो साल में जुड़ जाएगा सड़क सुविधा से।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–हिमाचल भवन मामले में उचित कानूनी उपाय करेगी प्रदेश सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा–हिमाचल भवन मामले में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई सुक्खू सरकार।
- नीति आयोग की भारत–जर्मनी साझेदारी के तहत हरित और सतत् विकास साझेदारी परियोजना प्रदेश में आरंभ।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगले दो वर्ष के भीतर कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दे रही है। डोडरा क्वार इसका ताजा उदाहरण है जो आजादी के बाद पहली बार पक्की सड़क सुविधा से जुडने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को चालू वित्त वर्ष के लिए दो हजार आठ सौ छः करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं और इसमे से अभी तक एक हजार दो सौ 38 करोड़ रूपए विभिन्न कार्यों पर खर्च हो चुके हैं।

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने के प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर उचित कानूनी उपाय करेगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार इस मामले की पुरजोर वकालत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार इस मामले की मजबूती से पैरवी करने में विफल रही। उन्होंने आर्बिट्रेशन से आए इस फैसले को चिंताजनक भी करार दिया।

जयराम ठाकुर

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल के सम्मान के प्रतीक हिमाचल भवन को आज कुर्क करने के आदेश हो गये हैं जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर खड़ा है और सरकार ने प्रदेश के हाईडल प्रोजेक्टों को भी बर्बाद कर दिया है।

विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश कोई नया मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले अदालत से कई बार आते रहते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये मामला सरकार पर देनदारियों को लेकर है और सरकार इस मामले में सुप्रीमकोर्ट जा सकती है या फिर इसे बातचीत से सुलझाने के लिए कानूनी राय ले सकती है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को हर मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा कि इससे पहले जंगी थोपन पावर प्रौजेक्ट को लेकर भी इसी तरह का फैसला आ चुका है।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज शिमला में भारत–जर्मनी साझेदारी के तहत हरित और सतत् विकास साझेदारी परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव ने इस मौके पर कहा कि नीति आयोग की ये परियोजना सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना सुनिश्चित करेगी। हिमाचल प्रदेश सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में देश का प्रमुख राज्य है। इसके दृष्टिगत ही हिमाचल को इस परियोजना की साझेदारी के लिए चुना गया है।

इंदिरा गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आज उनकी जयंती पर प्रदेश भर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य समारोह शिमला के रिज मैदान पर हुआ जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को विकास का मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार और बैंको का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की दूरदर्शी नितियों का प्रमाण है जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी इस मौके पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से टांडा और नाहन मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है।

चंद्र कुमार

कृषि व पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि सहकारिता समाज के आम और गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और संगठित तौर पर सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है।

चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली में आयोजित एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और पशुपालन से जुड़े परिवारों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता आंदोलन अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसी के दृष्टिगत सरकार कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिम गंगा योजना के लिए सरकार ने 5 सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

मक्की

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की की खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि इस कार्य के लिए 24 खरीद केंद्र बनाए गए है और किसानों से 30 रूपए प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदी जा रही है। हेमिस नेगी ने कहा है कि हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की और गेहूं के लिए पूरे देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है।

बिक्रम ठाकुर

भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल विफलताओं भरा रहा है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री सरकार के सत्ता में दो साल पूरे होने पर अपनी विफलताओं का भी जश्न मनाने जा रहे हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी शौचालय कर तो कभी समोसा प्रकरण की जांच करवा कर देश भर में हिमाचल की छवि को खराब किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया।

विकास कार्य

सोलन नगर निगम में काम कर रहे ठेकेदारों ने निगम के तहत होने वाले सभी विकास कार्यों को अनिश्तिकाल के लिए बंद कर दिया है। नगर निगम सोलन ठेकेदार युनियन के महासचिव कुलभूषण पंत ने कहा कि यूनियन ने ये फैसला निगम द्वारा ठेकेदारों के पैसे का भुगतान नहीं करने के चलते लिया है। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम सोलन ने बीते 6 महीनों से ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों का एक भी पैसा जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी हर बार पैसा न होने की बात का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में अब ठेकेदार बिना पैसे के काम करने में असमर्थ हो गए हैं।